

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ‘पारस’ पोर्टल की समीक्षा में दिए निर्देश

बाढ़ पीड़ितों को तुरंत मिले मुआवजा, विकास कार्यों और किसान पंजीयन में लाएं अद्यतन प्रगति

बकावंड जनता के गोठा
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘प्रोजेक्ट असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस सिस्टम’ (पारस) की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव श्री विकास शील, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह सहित राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पारस पोर्टल के गठन का मुख्य उद्देश्य राज्य में बुनियादी अधोसंरचना और विकास

परियोजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूरा कराना है। इसके लिए उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को आपसी समन्वय के साथ विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अधोसंरचना कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ हालिया भारी बारिश और बाढ़ से उपजी स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बस्तर और सुकमा सहित प्रदेश के सभी प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल व्यापक सर्वेक्षण कराने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहानि, पशुहानि, मकानों की क्षति और फसलों के नुकसान का त्वरित आकलन कर आरबीसी 6-4 के तहत तय समयसीमा के भीतर

मुआवजा वितरित किया जाए। इसके अलावा जिन परिवारों के मकान पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 हजार रुपये की तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने राहत शिविरों में भोजन और आवश्यक सुविधाएं अनवरत जारी रखने, जलजनित बीमारियों की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य शिविर सक्रिय रखने तथा पेयजल स्रोतों के क्लोरीनेशन के साथ क्लोरीन की गोलीयां बांटने के निर्देश दिए। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों, पुल-पुलियों, भवनों, बिजली लाईन और जलापूर्ति संरचनाओं की समयबद्ध मरम्मत के प्रस्ताव भेजने को कहा, जिससे जनजीवन जल्द सामान्य हो सके।



उन्होंने जनहानि के मामलों में 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' और फसलों के नुकसान में संबंधित बीमा योजनाओं के क्लेम भी शीघ्रता से स्वीकृत कराने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने किसान हित को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता निरूपित करते हुए जोर दिया कि धान बेचने वाला कोई भी

वास्तविक किसान एग्रीस्ट्रॉक पंजीयन से वंचित न रहे। पिछले वर्ष के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इस बार समय रहते शत-प्रतिशत पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे में पीछे चल रहे जिलों को विशेष ध्यान देने और खेतों में फसल खड़े रहने के दौरान ही सर्वेक्षण

तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिसके तहत मार्च 2027 तक 5 लाख घरों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक लगभग 1.10 लाख की प्रगति दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने तय समय में लक्ष्य हासिल करने के लिए वेंडर्स की संख्या बढ़ाने और बैंकों से बेहतर तालमेल बनाकर ऋण प्रक्रिया को सुगम बनाने के निर्देश दिए। अंत में उन्होंने सभी अधिकारियों से शासन की प्राथमिकताओं और जनकल्याणकारी योजनाओं को संवेदनशीलता व पूरी सजगता के साथ धरातल पर क्रियान्वित करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।

सेवा संकल्प अभियान: “सेवा मेरा योगदान” के तहत छात्रावासों के बच्चों ने किया पौधारोपण

बलरामपुर (जनता के गोठ) : सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत “सेवा मेरा योगदान” थीम पर जिले के छात्रावासों में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकासखंड बलरामपुर के प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास रनहत और विकासखंड वाड़फनगर के प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास बलंगी में विद्यार्थियों ने



उत्साहपूर्वक पौधे लगाए। इस दौरान बच्चों ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल कर उन्हें वृक्ष बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, हरियाली के महत्व और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि सेवा और सहभागिता की भावना उनके व्यवहार का हिस्सा बन सके।

सात माह बाद भी कलेक्टर के आदेश के अनुपालन पर उठे सवाल

ओड़गी में प्रभारी मंडल संयोजक के कार्यभार हस्तांतरण की स्थिति स्पष्ट नहीं, पत्रकार संघ ने जांच की मांग की।

जाहद अंसारी
सूरजपुर/ओड़गी। कलेक्टर कार्यालय आदिवासी विकास विभाग, सूरजपुर द्वारा 27 फरवरी 2026 को जारी आदेश के करीब सात माह बाद भी उसके अनुपालन की स्थिति स्पष्ट नहीं होने का मामला सामने आया है। आदेश क्रमांक 4257/स्था./आदि.वि./2024-25 के तहत ओड़गी विकासखंड के छात्रावासों एवं आश्रमों के सुचारु संचालन के लिए रूपलाल मिरी को प्रभारी मंडल संयोजक नियुक्त किया गया था। जारी आदेश के बिंदु क्रमांक 8 में तत्कालीन प्रभारी मंडल संयोजक मनोहर लाल गुप्ता को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर उनके मूल पदस्थ संस्था पूर्व माध्यमिक शाला दवना में भेजे जाने के निर्देश दिए गए थे। अब आदेश जारी होने के लगभग सात माह बाद कार्यभार हस्तांतरण एवं आदेश के पूर्ण अनुपालन की वास्तविक स्थिति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

पत्रकार संघ ने सौंपा आवेदन

मामले को लेकर पत्रकार संघ ने जिला कलेक्टर को आवेदन



पत्रकार संघ ने ओड़गी विकासखंड के छात्रावासों एवं आश्रमों की व्यवस्थाओं की स्थलीय जांच कराने की भी मांग रखी है। इसमें विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन, आवास, सुरक्षा, स्वच्छता, अनुशासन तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेने की बात कही गई है।

जांच के बाद स्पष्ट होगी वास्तविक स्थिति

संघ ने आदेश के अनुपालन में हुई देरी के कारणों की जांच, आवश्यक होने पर

सौंपकर संबंधित आदेश के अनुपालन की वर्तमान स्थिति की जांच कराने की मांग की है। संघ ने आवेदन में कहा है कि यदि आदेश के अनुरूप कार्यभार हस्तांतरण निर्धारित समय पर नहीं हुआ है, तो इसके कारणों की जांच कर संबंधित स्तर पर जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।

छात्रावास-आश्रमों की व्यवस्था की भी जांच की मांग

नियमानुसार कार्यवाई तथा कार्यभार हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण कराने की मांग की है। साथ ही जांच के निष्कर्ष और की गई कार्यवाई से अवगत कराने का आग्रह किया गया है। अब जिला प्रशासन की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि सात माह पुराने आदेश का वर्तमान में किस स्तर तक पालन हुआ है और यदि कोई विलंब हुआ है तो उसके कारण क्या रहे।

पानी टंकी का काम वर्षों से अधूरा, ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार पर लापरवाही का लगाया आरोप

बकावंड जनता के गोठा
विकासखंड के ग्राम वनकोंमार में जल जीवन मिशन के तहत प्रस्तावित पानी टंकी निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा है ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य के नाम पर अब तक केवल चार कॉलम के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, जिसके बाद काम आगे नहीं बढ़ा। ग्रामीणों के अनुसार करीब तीन वर्षों से निर्माण कार्य बंद पड़ा है, जिससे गांव में योजना के उद्देश्य के अनुरूप पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में घर-घर नल के माध्यम से पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। लेकिन मौके पर निर्माण की स्थिति बेहद खराब है। चार कॉलम के लिए गड्ढे खोदने के बाद संबंधित ठेकेदार द्वारा कार्य आगे नहीं बढ़ाया गया। लंबे समय से निर्माण स्थल



पर काम बंद होने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य की निगरानी और

प्रगति की जांच में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्तर पर भी लापरवाही बरती गई। उनका कहना

है कि यदि विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से स्थल निरीक्षण कर निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति

की समीक्षा की जाती तो कार्य इस स्थिति में नहीं पहुंचता। ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।

स्वीकृत राशि और भुगतान की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग

ग्रामीणों ने मांग की है कि संबंधित विभाग द्वारा वनकोंमार में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत

आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए स्कूली बच्चे

छिंदबहार स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने कलेक्टर को सौंपी राहत राशि

बकावंड जनता के गोठ
बस्तर संभाग में हाल ही में आई सदी की सबसे भयावक प्राकृतिक आपदा के बीच मानवीय संवेदना और सामाजिक एकजुटता की एक प्रेरक मिसाल सामने आई है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अर्नब के प्रभाव के कारण 23 से 26 सितम्बर के दौरान पूरे अंचल में लगातार मूसलाधार बारिश हुई थी। इस भीषण वर्षा के चलते पड़ोसी राज्य ओड़िशा स्थित खातीगुड़ा और मुदान बांध के गेट खोलने पड़े, जिससे नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया और बस्तर में आई भीषण बाढ़ ने पिछले 50 वर्षों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। इस जलप्रलय



से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और निचले इलाकों में भारी तबाही मची है।

आपदा की इस विषम परिस्थिति में प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए दरभा विकास खंड के ग्राम छिंदबहार स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के

विद्यार्थियों और शिक्षकों ने संवेदनशीलता की अनूठी मिसाल पेश की है। स्कूल के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट स्थित प्रेरणा कक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक के दौरान पहुंचकर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा से मुलाकात की और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए

अपनी ओर से 5,001 रुपये की आर्थिक सहायता राशि सौंपी। इस संकट की घड़ी में एक ग्रामीण सरकारी स्कूल के बच्चों और शिक्षकों द्वारा की गई इस आत्मीय पहल की कलेक्टर ने भूरि-भूरि प्रशंसा की, जिसकी पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है।

आपदा पीड़ितों की मद हेतु आगे आया उत्कल समाज, बाढ़ पीड़ितों की मद के लिए कलेक्टर को सौंपा 21 हजार रुपये का चेक

बकावंड जनता के गोठा, 29 सितंबर 2026/ बस्तर संभाग में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा और बाढ़ के संकट को देखते हुए सामाजिक संगठन पीडित मानवता की सेवा में आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्कल समाज बस्तर संभाग ने संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हुए मुख्यमंत्री बाढ़ आपदा राहत कोष में 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। समाज ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि राहत शिविरों के संचालन के साथ-साथ अन्य आवश्यक कार्यों में प्रशासन का हाथ बंटाने के लिए सहयोग राशि दी जाएगी।

इसी निर्णय के परिपालन में मंगलवार को उत्कल समाज का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा और बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा को 21 हजार रुपये का चेक सौंपा। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तन्मय खन्ना, अपर कलेक्टर श्री सीपी बघेल और नगर निगम आयुक्त श्री प्रवीण वर्मा सहित अन्य



प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने समाज की इस मानवीय पहल और तत्परता की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया।

चेक सौंपने के दौरान उत्कल समाज बस्तर संभाग के अध्यक्ष राजेश दास, सचिव सुमित

महापात्र, उपाध्यक्ष मथुरा तिवारी, कोषाध्यक्ष मनोज महापात्र, संगठन सचिव रमेश नंद, कार्यालयीन सचिव अच्युत सामंत तथा कार्यकारिणी सदस्य अतुल दास सहित समाज के अन्य गणमान्य सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

दामागुड़ा में सेवा संकल्प अभियान के तहत न्यौता भोज एवं पोषण पखवाड़ा

उपसरपंच ज्योति बघेल ने पूजा-अर्चना कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ, माताओं को पोषण के प्रति किया जागरूक

भुजबल बघेल
बकावंड जनता के गोठा
विकासखंड बकावंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पाहुर्बेल के आश्रित ग्राम दामागुड़ा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र डोंगरीगुड़ा में 28 सितंबर को सेवा संकल्प अभियान के तहत न्यौता भोज एवं पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम पंचायत पाहुर्बेल की उपसरपंच श्रीमती ज्योति बघेल ने विधिवत पूजा-अर्चना कर किया।

कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता सुहाती कश्यप, सहायिका गुवावरी बघेल, परियोजना अधिकारी श्रीमती अभिलाषा यादव, सुपरवाइजर श्रीमती रमशिला देवांगन, शिवानी जोशी, राधिका कुमार सहित पंचायत क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं, मितानिन, गर्भवती एवं



शिशुवती माताएं, पंचगण तथा वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने सामूहिक भोज में शामिल होकर कार्यक्रम में सहभागिता निभाई।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित माताओं एवं महिलाओं को बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूक किया गया। बच्चों के भोजन में पौष्टिक एवं संतुलित आहार शामिल करने तथा उनके

स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए परिवार और समुदाय की सक्रिय सहभागिता के महत्व पर भी जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए पोषण संबंधी आदतों को अपनाने तथा समाज में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया।

प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में दुर्ग सांसद विजय बघेल ने गिनाई तीन वर्ष की उपलब्धियां

अंचल वर्मा – दुर्ग, उत्तराई।

जनता के गोठा
भिलाई। न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई नगर द्वारा नेहरू भवन, सुपेला में 'प्रेस से मिलिए' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने मां सरस्वती के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल गुप्ता सहित पत्रकारों ने सांसद विजय बघेल का पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया। अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने प्रेस क्लब की ओर से मांग-पत्र भी सांसद को सौंपा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद विजय बघेल ने अपने कार्यकाल के तीन वर्षों की उपलब्धियों और क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज की घटनाओं और जनसमस्याओं को साक्ष्य के साथ समाज के सामने प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पत्रकारों के बीच आकर संवाद करना उनके लिए सौभाग्य की बात है।

सांसद ने कहा कि दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण



दोनों क्षेत्र शामिल हैं। क्षेत्र में चार नगर निगम आते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ मिलकर लगातार कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भिलाई क्षेत्र में श्रमिकों की सुविधाओं, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य हुए हैं। श्रमिकों के लिए अस्पताल की सुविधा, केंद्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय जैसे महत्वपूर्ण कार्य उनके कार्यकाल में आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रलाल चंद्राकर



अस्पताल की सीटों में वृद्धि के लिए भी केंद्रीय स्तर पर प्रयास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सीटों की संख्या बढ़ी है।

सांसद ने जल संरक्षण को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'जल ही जीवन है' के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना जरूरी है। आने वाले समय में पानी की समस्या गंभीर हो सकती है, इसलिए प्रत्येक परिवार को अपने आवास के साथ वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि नगर निगम में वाटर हार्वैस्टिंग से संबंधित कार्यों के लिए राशि उपलब्ध है।

उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' जैसे अभियानों के साथ पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण को

जोड़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सांसद ने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में उनका प्रयास है कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर वे लगातार शासन स्तर पर प्रयास करते रहें।

उन्होंने बताया कि क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित खेल गतिविधियों में बड़ी संख्या में पंजीयन हुआ है। सांसद मेला-मंडई जैसे आयोजनों के माध्यम से भी स्थानीय प्रतिभाओं और संस्कृति को मंच देने का प्रयास किया गया है।

सांसद ने कहा कि दिल्ली में वे क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों से जुड़े दस्तावेजों पर लगातार हस्ताक्षर करारकर संबंधित मंत्रालयों तक विषय पहुंचाते हैं। रेलवे यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए भी वे लगातार प्रयास करते हैं।

कार्यक्रम में प्रेस क्लब अध्यक्ष अनिल गुप्ता, दिलीप वर्मा, सुनील चौहान, यदुनंदन पंडा, जय प्रकाश आर्य, जोगिंदर सिंह, गौरीकरण निषाद, दिनेश चौहान, के. मोहन राव, गोपाल देवांगन, पी. मोहन, सर्वेश सिंह, सुरेंद्र ठाकुर, राजकुमार आर्य, योगेश शर्मा, सोनू यादव सहित पत्रकारगण उपस्थित रहे।

शिकायत के सत्यापन के बाद ACB ने बिछाया ट्रैप, संयुक्त जिला कार्यालय में अचानक दबिश से मचा हड़कंप

22 हजार की रिश्त लेते नागरिक आपूर्ति विभाग का अधिकारी गिरफ्तार

बलरामपुर : नागरिक आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकारी विद्यासागर गोपाल को कथित तौर पर 22 हजार रुपये की रिश्त लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मंगलवार को संयुक्त जिला कार्यालय स्थित विभागीय कार्यालय में, छक्क की अचानक दबिश से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, किसी शासकीय कार्य के एवज में रिश्त मांगे जाने की शिकायत ACB को प्राप्त हुई थी। शिकायत का सत्यापन करने के बाद ACB की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप की कार्रवाई की। जैसे ही अधिकारी ने कथित रूप से रिश्त की रकम स्वीकार की, टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया।



बंद कमरे में पूछताछ, दस्तावेजों की भी जांच कार्रवाई के बाद ACB की

टीम ने अधिकारी के कक्ष को अपने नियंत्रण में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। टीम द्वारा विभागीय

दस्तावेजों और संबंधित रिकॉर्ड की भी जांच किए जाने की जानकारी सामने आई है। कार्रवाई की खबर

फैलते ही नागरिक आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों में अफ़ा-तफ़री का माहौल बन गया।

शिकायत से ट्रैप तक, ACB की पूरी कार्रवाई बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता की सूचना के आधार पर, छक्कने पहले मामले का सत्यापन किया और शिकायत सही पाए जाने के बाद ट्रैप की योजना बनाई। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत रिश्त की रकम के साथ अधिकारी को पकड़ा गया।

फिलहाल ACB की कार्रवाई जारी है। मामले में दस्तावेजी जांच और पूछताछ पूरी होने के बाद ही पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी सामने आएगी। ACB के अधिकारिक बयान के बाद ही रिश्त मांगने और कार्रवाई से जुड़े सभी तथ्यों की अंतिम पुष्टि हो सकेगी।

जनपद पंचायत शंकरगढ़ में सचिव, रोजगार सहायक एवं बीएफटी की समीक्षा बैठक सम्पन्न



सेवा सेतु शिविर की तैयारियों पर दिए निर्देश

बलरामपुर (जनता के गोठ) : जनपद पंचायत शंकरगढ़ के सभागार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी(मनरेगा) ने विकासखंड के समस्त सचिवों, रोजगार सहायकों और बेयरफ्ट

तकनीशियनों (बीएफटी) की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले सेवा सेतु शिविरों की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का शिविर में ही त्वरित समाधान हो सके।

बैठक में वीबी-जी राम जी के

अंतर्गत कार्यस्थलों पर श्रमिकों की उपस्थिति की विस्तृत समीक्षा कर इसे बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही बालिका शौचालयों के निर्माण की प्रगति की जानकारी लेकर कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। इस दौरान वीजीपीपी के संबंध में प्रशिक्षण देकर इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक जानकारी और निर्देश भी दिए गए।

गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस, जिले की सभी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद

बलरामपुर (जनता के गोठ) : कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 तथा वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के अंतर्गत शासन के निर्देशानुसार गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन जिले की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें तथा अहाता अनुज्ञप्तिपूर्ण: बंद रहेंगी और मदिरा के विक्रय, धारण एवं परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

कलेक्टर ने आदेश में निर्देश दिए हैं कि शुष्क दिवस पर पूरे जिले में मदिरा के अवैध निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय-विक्रय, भंडारण और तस्करी पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए। शिकायत मिलने पर तत्काल सख्ती से रोक लगाते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर, बाड़फणगर एवं राजपुर वृत्त के आबकारी उपनिरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र की सभी मदिरा दुकानें बंद काराकर विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

बाढ़ प्रभावित ग्राम गुमड़ेल एवं कुरुषपाल पहुंचे सरपंच संतोष कश्यप

पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर जाना हालचाल, समस्याओं का लिया जायजा

बकावंड जनता के गोठ। विकासखंड बकावंड के ग्राम पंचायत छोटे देवड़ा के सरपंच संतोष कुमार कश्यप ने बाढ़ प्रभावित ग्राम गुमड़ेल एवं कुरुषपाल का भ्रमण कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी वर्तमान स्थिति का जायजा लिया।

भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद भी अनेक परिवार कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। कई घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। घरों में नमी और कीचड़ जमा होने के कारण लोगों को रहने, बैठने और सोने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को काफी दिक्कतें हो रही हैं।

संतोष कुमार कश्यप ने प्रभावित परिवारों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में



पद्धति से ढेंकी द्वारा हाथ से कूटा गया है, जो शत-प्रतिशत प्राकृतिक और अनपॉलिशड है। आधुनिक मशीनों की पॉलिशिंग से मुक्त होने के कारण इसके आवश्यक पोषक तत्व और रेशे पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं, जिससे इसमें परंपरा का स्वाद, सेहत का साथ और गांव की सोंधी खुशबू का अनुूठा संगम देखने को मिलता है। सीईओ श्री तन्मय खन्ना एवं अन्य वरिष्ठ

अधिकारियों द्वारा की गई इस पहल ने समूह की महिलाओं का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया है। अधिकारियों का मानना है कि पारंपरिक और जैविक खान-पान न केवल पोषण की दृष्टि से उत्तम है, बल्कि ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने का सशक्त माध्यम भी है। अधिकारियों की इस सीधी खरीदारी से ग्रामीण महिलाओं को अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिल रहा है।



समाज के सभी लोगों को एकजुट होकर प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। जनसेवा केवल दायित्व नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का माध्यम है। संकट की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों का सहयोग करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने ग्रामीणों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ऐसी विषम परिस्थितियों में पूरा

समाज प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है। सभी के सहयोग और सहभागिता से प्रभावित परिवार इस संकट से उबर सकेंगे।

इस दौरान ग्रामीणों ने बाढ़ से हुए नुकसान एवं अपनी अन्य समस्याओं से सरपंच को अवगत कराया। भ्रमण के दौरान स्थानीय ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

महिला आयोग की जनसुनवाई: सरगुजा संभाग के 25 मामलों की हुई सुनवाई, 06 प्रकरण नस्तीबद्ध

अंबिकापुर 7 29 सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता और संभाग प्रभारी श्रीमती लक्ष्मी शुक्ला की गरिमामयी उपस्थिति में मंगलवार को अंबिकापुर में सरगुजा संभाग स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। महिलाओं को त्वरित न्याय व राहत दिलाने के उद्देश्य से आयोजित यह संभाग स्तर की पहली तथा प्रदेश स्तर की 9वीं जनसुनवाई थी।

जनसुनवाई में सरगुजा संभाग के 06 जिलों- सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर एवं मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से आए कुल 25 प्रकरणों की गहन सुनवाई की गई। इनमें से 06 मामलों का त्वरित निराकरण करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया गया।



प्रकरणों पर प्रमुख निर्देश एवं कार्रवाई

- मानसिक प्रताड़ना मामला: मानसिक उत्पीड़न से जुड़े एक गंभीर प्रकरण में आयोग ने संबंधित जिला कलेक्टर को स्वयं जांच कर प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
- कार्यस्थल पर उत्पीड़न: स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित

कार्यस्थल पर प्रताड़ना के एक मामले में सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया।

- घरेलू हिंसा एवं अन्य मामले: घरेलू हिंसा व मानसिक उत्पीड़न के प्रकरणों में संबंधित जिलों के संरक्षण अधिकारियों को मौके पर जांच कर आयोग के समक्ष रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी दी गई है।



अधिकारियों की मौजूदगी जनसुनवाई के दौरान प्रशासनिक व विधिक दल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इनमें मुख्य रूप से:

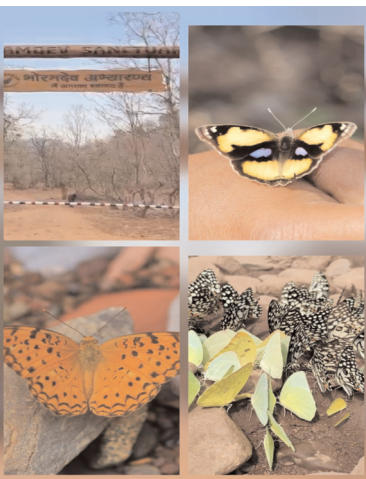
- प्रशासनिक अधिकारी: जिला कार्यक्रम अधिकारी जे.आर. प्रधान, नोडल अधिकारी एवं उप निरीक्षक विजय गुप्ता।
- संरक्षण अधिकारी: श्रीमती

सुलेखा कश्यप (सरगुजा), श्रीमती शिखा वामा (जशपुर), श्रीमती वित्तबाला सिन्हा (कोरिया), श्रीमती इन्दुकुवारी तिवारी (सूरजपुर) एवं श्रीमती सुमित्रा सिंह (बलरामपुर)।

- अन्य टीम: विधिक सहायता टीम के सदस्य तथा संभाग के सभी जिलों की 'सखी वन स्टॉप सेंटर' की केंद्र प्रशासिकाएं।

कवर्धा। कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभ्यारण्य में प्रकृति और जैव विविधता को करीब से जानने-समझने का अनुूअ अवसर मिलने जा रहा है। यहां भोरमदेव बटरफ्लाई मीट सीजन-3 का आयोजन चार अलग-अलग वीकेंड में किया जाएगा।

आयोजन में प्रकृति प्रेमियों, वन्यजीव विशेषज्ञों, फोटोग्राफों और विद्यार्थियों को भोरमदेव के जंगलों में पाई जाने वाली तितलियों की विभिन्न प्रजातियों को करीब से देखने और उनके व्यवहार को समझने का अवसर मिलेगा।



जंगल और वन्यजीवों के प्रति लोगों की समझ बढ़ाने के साथ-साथ प्रकृति आधारित पर्यटन को भी प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

चार चरणों में आयोजित होने वाला यह बटरफ्लाई मीट स्थानीय जैव विविधता को देश-दुनिया के प्रकृति प्रेमियों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। इससे इको-टूरिज्म और नेचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की उमीद है।

मौजूद तितली प्रजातियों की पहचान, उनके प्राकृतिक आवास और क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। विशेषज्ञों और प्रतिभागियों के माध्यम से तितलियों के जीवनचक्र, उनके व्यवहार तथा पर्यावरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने का प्रयास किया जाएगा।

सेवा संकल्प अभियान: आंगनबाड़ी केंद्रों में धूमधाम से मना आंगन मिलन उत्सव, बच्चों को बांटे गए खिलौने

बलरामपुर (जनता के गोठ) : सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया। जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, माताओं और बच्चों की सहभागिता से आयोजित इन कार्यक्रमों में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता के साथ न्योता भोज, प्रतियोगिताएं और सम्मान समारोह हुए। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र भासनी बंद-पचावल एवं भेलवाडीह में डीपीएम द्वारा बच्चों को खिलौने वितरित किए गए। परियोजना वाडुफणगर के सेक्टर बरतीकला अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र शिवरी खास, सेक्टर इंजानी के ग्राम भगवानपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र केनापारा-2 तथा सेक्टर चलगली ओदारी में आंगन मिलन उत्सव मनाया गया। सेक्टर बरसतपुर के ग्राम पंचायत मिथलापुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पलगीपारा में सरपंच द्वारा न्योता भोज कराया गया और 6 कार्यक्रमों, सहायिकाओं तथा एक मितांन दीदी को शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया



गया। यहां महिलाओं के लिए कुर्सी दौड़ और घड़ा फेड़ तथा बच्चों के लिए स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता आयोजित कर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। जनप्रतिनिधियों ने 'मेरी पौष्टिक थाली' थीम पर चर्चा कर संतुलित आहार का महत्व बताया। परियोजना रामचंद्रपुर के सेक्टर कुरतुडीह में पोषण माह के साथ आंगन मिलन उत्सव मनाया गया। परियोजना बलरामपुर के

सेक्टर पस्ता अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र चिलमा में उप सरपंच, पंचगण, ग्राम मुखिया और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ। यहां मेरी पौष्टिक थाली, स्थानीय व्यंजनों तथा साग-सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई गई और न्योता भोज कराया गया। कार्यक्रम, सहायिका, मितांन और स्वस्थ शिशु की माताओं को सम्मानित किया गया। ग्रामीणों को स्वच्छता, पोषण,

स्वास्थ्य शिक्षा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) और बाल संदर्भ शिविर की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से स्वास्थ्य शिविर लगाकर परिवार नियोजन, टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड और बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति भी जागरूक किया गया।

अन्य प्रांत की मदिरा के अवैध परिवहन के मामले में दो आरोपियों को कारावास एवं अर्थदंड

कवर्धा, आबकारी आयुक्त एवं कलेक्टर तुलिका प्रजापति के निर्देश तथा जिला आबकारी अधिकारी मुकेश पाण्डेय के मार्गदर्शन में जिले में अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आबकारी चेकपोस्ट चिल्थी में अन्य प्रांत की मदिरा के अवैध परिवहन के दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय द्वारा आरोपियों को कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

प्रकरण क्रमांक 180/2025, 4 फरवरी 2025 में आरोपी राजेश जमरे पिता सोमलाल जमरे को न्यायालय द्वारा 18 माह के साधारण कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं प्रकरण क्रमांक 181/2025, 12 फरवरी 2025 घनश्याम सिंह राजवीर सिंह पिता घनश्याम सिंह को 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी श्री मुकेश पाण्डेय ने बताया कि 4



फरवरी 2025 को आबकारी उपनिरीक्षक श्री अभिनव कुमार रायजादा द्वारा आबकारी चेकपोस्ट चिल्थी में वाहन जांच के दौरान आरोपी राजवीर सिंह के अधिपत्य वाले आईशर भारी वाहन क्रमांक आरजे 11 जीसी 2927 से मध्यप्रदेश निर्मित लेबल लगी 19,650 नग पाव देशी प्लेन मदिरा, जिसकी कुल मात्रा 1,800 बल्क लीटर बरामद की गई। वाहन से कुल 4,770 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गई थी। दोनों आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 यथा संशोधित की धारा 34(1)(क), 34(2),

को चिल्थी आबकारी चेकपोस्ट में वाहन जांच के दौरान आरोपी राजवीर सिंह के अधिपत्य वाले आईशर भारी वाहन क्रमांक आरजे 11 जीसी 2927 से मध्यप्रदेश निर्मित लेबल लगी 16,500 नग पाव देशी प्लेन मदिरा, जिसकी कुल मात्रा 2,970 बल्क लीटर, तथा 10,000 नग पाव गोवा हिस्की, जिसकी कुल मात्रा 3,537 बल्क लीटर, तथा 5,000 नग पाव गोवा हिस्की, जिसकी कुल मात्रा 900 बल्क लीटर बरामद की गई। इस प्रकार कुल 4,437 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गई थी।

36 एवं 59(क) के तहत गैर-जमानती प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था।

न्यायालय में प्रस्तुत किया गया अभियोग पत्र

प्रकरण क्रमांक 1520/2025, शासन विरुद्ध राजेश जमरे में विवेचना पूर्ण होने के बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कवर्धा द्वारा आरोपी राजेश जमरे को 18 माह के साधारण कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इसी प्रकार दण्डिष्क प्रकरण क्रमांक 1566/2025, शासन विरुद्ध राजवीर सिंह में विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कवर्धा द्वारा आरोपी राजवीर सिंह को 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

संक्षिप्त

समाचार

3 दिन की हड़ताल के दौरान नहीं लगेगा कोई एटीएम चार्ज

है। दिल्ली, एच.सी.सी.। आगामी 28 सितंबर से शुरू होने वाली बैंक कर्मचारियों की तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए देश के बैंकिंग क्षेत्र ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक सहित सभी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक बड़ा फैसला लिया है। इन बैंकों ने 28 से 30 सितंबर 2026 तक सभी एटीएम ट्रांज़ेक्शन फीस को पूरी तरह से माफ करने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद ग्राहक तक मात्र फीस मुफ्त सीमा समाप्त होने के बाद भी देश के किसी भी बैंक के एटीएम से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कैश निकाल सकेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी पुष्टि करते हुए लिखा, 'आपकी सुविधा हमारी प्राथमिकता है। 28 से 30 सितंबर तक पूरे भारत में किसी भी बैंक के एटीएम पर ट्रांज़ेक्शन चार्ज माफ कर दिए गए हैं।' यह प्रस्तावित हड़ताल सोमवार (28 सितंबर) से शुरू हो रही है, जो टीक वीकेंड (26 और 27 सितंबर) के बाद आती है। यदि सरकार और रिजर्व बैंक 5 दिन पर कदम नहीं उठाते, तो देश में लगातार 5 दिनों तक बैंकिंग कामकाज पूरी तरह बंद हो जाता। इसका देश के व्यापार, वेतन भुगतान और अर्थव्यवस्था पर बहद बुरा असर पड़ सकता था। इसी संकट से निपटने और आर्थिक गतिविधियों को सुचारु रखने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने एक निर्देश जारी किया है। इसके तहत, कन रिविवा को देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आम दिनों की तरह पूरी तरह खुले रहेंगे। आरबीआई ने सभी बैंक शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों और करंसी चेन्ट को रिविवा को भी सामान्य रूप से संचालित करने की विशेष मंजूरी दी है, ताकि लोग हड़ताल से पहले अपने जरूरी काम निपटा सकें। सभी प्रमुख बैंकों ने स्पष्ट किया है कि हड़ताल का असर केवल भौतिक बैंक शाखाओं के कामकाज पर पड़ सकता है। आम जनता के लिए डिजिटल लेनदेन के सभी रास्ते खुले रहेंगे। यह देशव्यापी हड़ताल 'यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस' के आह्वान पर बुलाई गई है, जो बैंकिंग कार्यबल के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। बैंक कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांगों में हफ्ते में केवल 5 दिन काम की व्यवस्था लागू करना, पेशा में सुधार, सभी पेंशनभोगियों के लिए समान महंगाई भत्ता फॉर्मूला और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बुनने का विकल्प देना शामिल है। चूंकि यह हड़ताल छमाही वलोजिंग के समय हो रही है, इसलिए इसका असर गहरा सकता है।

एनटीपीसी और ईडीएफ ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया समझौता

नई दिल्ली, एजेसी। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी और इंडीएफ पावर सॉल्यूशंस इंडिया ने भारत में पंड स्ट्रेजेज, जलविद्युत और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास, स्वामित्व तथा संचालन के लिए साझेदारी की है। एनटीपीसी एक बयान में कहा कि दोनों कंपनियों के बीच 50-50 का एक संयुक्त उद्यम (जंजी) बनाया गया है। यह संयुक्त उद्यम भारत और पड़ोसी देशों में परियोजनाओं पर काम करेगा। समझौते पर 25 सितंबर को एनटीपीसी के चेयरमैन गुर्देप सिंह और इंडीएफ एस्पए के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीओओ) बर्नार्ड फोंटाना की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। इस रणनीतिक साझेदारी के तहत एनटीपीसी और फ्रांस की बिजली कंपनी इंडीएफ की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई इंडीएफ पावर सॉल्यूशंस मिलिटर कम कार्बन उत्सर्जन वाले बिजली संयंत्रों के विकास, निर्माण और संचालन के साथ-साथ मिट डिस्थरता बढ़ाने वाले समाधानों तथा पारेषण परिसंपत्तियों पर काम करेगी। एनटीपीसी ने कहा कि यह साझेदारी भारत के 2036 तक पंड स्ट्रेजेज (भंडारण) परियोजनाओं की 100 गीगावाट स्थापित क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है।

द्वितीयः

आम लोगों को झटका, त्योहारी सीजन से पहले एसी-टीवी सहित इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के दाम बढ़ेंगे



तीन से चार प्रतिशत बढ़ने जा रही हैं। हालाँकि, कुछ कंपनियाँ अभी स्थिति का आकलन कर रही हैं। कई कंपनियों का मानना है कि कीमत बढ़ने से मांग पर असर पड़ सकता है। वहीं कुछ अन्य की राय है कि कीमत वृद्धि का असर सीमित रहेगा, क्योंकि डीलर और वितरकों के पास पहले ही पुराने दाम का स्टॉक है।

ब्लू स्टार, गोदेरज अप्लायंसेज, हायर, डेकिन और सुपर

प्लास्टीनक्स समेत कई कंपनियों विभिन्न श्रेणियों में कीमतें बढ़ाने का प्रयास कर चुकी हैं। एलजी और सैमसंग बाँझ होम कम्प्यूटर, जो हितावी ब्रांड के एयर कंडीशनर का कारोबार करती है, ने भी एसी की कीमतों में करीब पाँच प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। पैनासोनिक अभी कीमत बढ़ाने का लेकर स्थिति का आकलन कर रही है।

नवरात्रि से दिवाली तक आती है बिक्री में तेजी

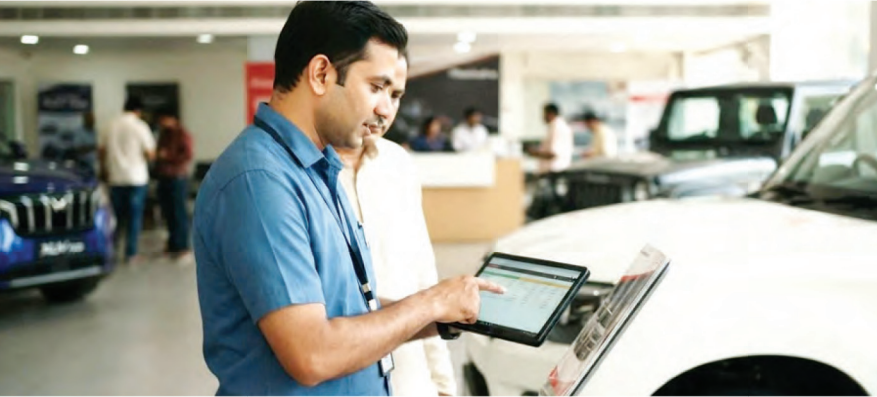
आमतौर पर नवरात्रि से दिवाली तक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों की बिक्री होती जाती है और कंपनियाँ आकर्षक छूट एवं ऑफर देती हैं। ऐसे में बढ़ी हुई कीमतें ग्राहकों के खरीद निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि, कंपनियाँ का कहना है कि डीलर और वितरकों के पास अगस्त-सितंबर में पुराने दाम पर खरीदा गया प्यास स्टॉक मौजूद है। इसलिए दिवाली तक कुछ उपकरण पुराने दाम पर उपलब्ध रह सकते हैं। इसके बाद नए दाम बाजार में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने की संभावना है। उद्योग की रिपोर्ट के अनुसार ओणम से लेकर दशहरा और दिवाली तक का त्योहारी दौर घरेलू उपकरण विनिर्माताओं की सालाना बिक्री में करीब 30 से 40 प्रतिशत का योगदान देती है। ऐसे में कंपनियों के लिए बढ़ती लागत और त्योहारी मांग के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती होगी।

महिंद्रा फिर बढ़ा सकती है एसयूवी के दाम, अगले दो हफ्ते में होगा अंतिम फैसला

नई दिल्ली, एजेसी। महिंद्रा एंड महिंद्रा बढ़ती लागत के कारण अपने एसयूवी पोटफोलियो की कीमतें फिर बढ़ा सकती है, जिसका फैसला अगले दो सप्ताह में होगा। इसके बावजूद कंपनी को त्योहारी सीजन में मजबूत मांग बने रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, महिंद्रा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देते हुए अपनी कुल मासिक उत्पादन क्षमता 84,000 वाहन तक पहुंचाएगी।

महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (एसयूवी) पोर्टफोलियो की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर सकती है। कंपनी जिस कीमतों में हालिया वृद्धि को देखते हुए अगले वर्ष कीमतें बढ़ाएगी, उससे इस संबंध में फैसला ले सकती है। महिंद्रा एसयूवी के सात प्रभाग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीओओ) नलीनिकांत गोल्ताला ने कहा कि पीटीआई-के साथ साक्षात्कार में कहा कि कंपनी इस साल जनवरी, अप्रैल और जुलाई में पहले ही तीन बार कीमतों बढ़ा चुकी है। जुलाई में एसयूवी की कीमतों में करीब 2.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। उन्होंने कहा कि जिस कीमतों में हालिया वृद्धि की देखते हुए कंपनी अगले कुछ सप्ताह में तय करेगी कि एक और बढ़ोतरी की जरूरत है या नहीं। गोल्ताला ने कहा कि पीटीआई-के मुताबिक, कीमतों में हालिया बढ़ोतरी का ग्राहकों की प्रतिक्रिया और बुकिंग पर फिलहाल कोई खास असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि महिंद्रा के वाहन अब भी माल पर सेवा कर

(जीएसटी) में कटौती से पहले की कीमतों के मुकाबले कम कीमत पर उपलब्ध हैं, जिससे मांग मजबूत बनी हुई है।



उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन में महिंद्रा के साथ-साथ पूरे वाहन उद्योग में मांग मजबूत रहने की उम्मीद है। उन्होंने इसकी वजह जैसीएस्टी कटौती के बाद कीमतों में कमी और फ्लैटपोर्टफोलियो में बदलाव को बताया। हाइब्रिड प्रौद्योगिकी के बारे में गोल्लागुंडा ने कहा कि महिंद्रा का मुख्य ध्यान इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पर है। उन्होंने कहा कि यदि नियामकीय व्यवस्था में बदलाव होता है तो कंपनी उसके अनुरूप अपनी रणनीति बदल सकती है, लेकिन फिलहाल

बिजलीचालित परिवहन कंपनी की प्राथमिकता है।
कंपनी की उत्पादन क्षमता के बारे में उन्होंने बताया कि महिंद्रा के पास फिलहाल हर महीने करीब

उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन में महिंद्रा के साथ-साथ पूरे वाहन उद्योग में मांग मजबूत रहने की उम्मीद है। उन्होंने इसकी वजह जैसीएस्टी कटौती के बाद कीमतों में कमी और फ्लैटपोर्टफोलियो में बदलाव को बताया। हाइब्रिड प्रौद्योगिकी के बारे में गोल्लागुंडा ने कहा कि महिंद्रा का मुख्य ध्यान इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पर है। उन्होंने कहा कि यदि नियामकीय व्यवस्था में बदलाव होता है तो कंपनी उसके अनुरूप अपनी रणनीति बदल सकती है, लेकिन फिलहाल

60,000 पारंपरिक इंजन (आईसीई) वाहन और 8,000 इलेक्ट्रिक वाहन की उत्पादन क्षमता है।

मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत तक आईसीई क्षमता बढ़कर 70,000 और ईवी क्षमता बढ़कर 12,000 वाहन प्रति माह करने की योजना है। इस तरह कुल मासिक क्षमता करीब 84,000 वाहन तक पहुंच जाएगी। गोएल्लगुटा ने कहा कि कंपनी अगली दो तिमाहियों में कई नए उत्पाद बढलाव के साथ पेश करेगी और दो नए मॉडल उतारेगी।

अब साबुन और टूथपेस्ट पर भी लगेगा वेज-नॉनवेज का मार्क, सरकार ने बदले नियम

हेदराबाद, एजेसी। केंद्र सरकार ने भारतीयों की सहूलियत और धार्मिक प्रभावों को धर्मोत्थानियों के अधिकार को मानवत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। लीगल मेट्रोलाजी (कवड क्मोडिटीज) रूस्स, 2011 में हाल ही में एक गण संशोधन के तहत अब दैनिक उपयोग में प्रसाधन सामग्रियों पर शाहकारी या मंसाहार करने का प्रतीक चिन्ह लगाना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। यह नया नियम अधिसूचन में जारी होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू होगा है। नए नियमों के मुताबिक, अब सभी प्रसाधन सामग्रियों को अपने उत्पादों जैसे साबुन, शैम्पू, पेंसिल, कोसैटिक्स और अन्य प्रसाधन सामग्रियों के मुख्य डिस्प्ले पैन्ल पर स्पष्ट रूप से

प्रतीक चिन्ह देना होगा
यह नियम पहले वर्ष 2014 में नियम 6(8)



के तहत लाया गया था, जिसे अब तकनीकी तौर पर संशोधित कर नियम 6(4ए)में स्थानांतरित किया गया है. हालांकि, इन दावों के वैज्ञानिक

सत्यापन को लेकर ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और लीगल मेट्रोलाजी विभाग के बीच कुछ मुरावे नीतिगत मतभेद रहे हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक एकीकृत व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया है.

पैकेज्ड उत्पादों के इस राष्ट्रीय नियम के बीच, राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी खान-पान उद्योग में बदलाव की घोषणा की है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन द्वारा तैयार किए गए नए मानकों के तहत, प्रदेश के सभी होटलों, रेस्तरां और फास्ट-फूड काउंटरों में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को एक-दूसरे से पूरी तरह अलग रखने की व्यवस्था नवंबर 2026 से अनिवार्य होने जा रही है।

अमेजन, फिलिपकार्ट पर 10-10 लाख व जियोमार्ट पर पांच लाख का जुर्माना, सीसीपीए ने की कार्रवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय उपभोक्ता
रक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने अमेजन
नियमपत्र पर 10-10 लाख रुपये व
फिलॉसॉफी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना
गाया है। तीनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर
हाइलॉसिनिन हाईसोल्ड नामक बिना
जीवन वाले कृषि-रसायन उत्पाद को
चौथे और उसका विज्ञापन करने का आरोप
22 सितंबर के एक अलग आदेश में
उपभोक्ता संरक्षण नियामक ने तीनों ई-
कॉमर्स कंपनियों को उस उत्पाद की बिक्री
को विज्ञापन तुरंत रोकने का निर्देश दिया है
उसे उसके एक्टिव इंड्रिडिअल के रसायन
मय या उसके कंपोजिशन का खुलासा किए
बिना बेचा जा रहा था। सीसीपीए ने इन
नेटवर्कर्स को ऐसे उत्पाद की लिस्टिंग
करने के लिए सेल्फ-ऑडिट करने का भी
निर्देश दिया जो मौजूदा कानूनों का उल्लंघन
करते हैं या उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए
अवसर पैदा करते हैं। नियामक ने तीन
कंपनियों से 15 दिनों के भीतर अपुलान
पोर्ट जमा करने को कहा है।



दरअसल, सीसीपीए को केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से मिली एक शिकायत के बाद यह जांच शुरू हुई। इसे मूल रूप से क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीसीएफआई) ने दर्ज कराया था। जांच के दौरान कृषि मंत्रालय ने सीसीपीए को बताया कि साइक्लोसिमेनोन नाम का कोई भी रसायन

कोटनाशक अधिनियम-
1968 में अनुसूची
शामिल नहीं है। इसका
मलबत है कि इस उत्पाद
की बिजली और मार्केटिंग
में कानून के तहत जरूरी
सुरक्षा, बायो-एफिकेसी,
गुणवत्ता और कानूनी
जांच को नजरअंदाज
किया गया। सीसीपीए ने
उपाय कि मार्केटप्लेस ने
पाया कि लिस्टिंग को
लाइव करने से पहले
उसके रेगुलेटरी स्टेटस
की पर्याप्त स्वतंत्र जांच
नहीं की थी पोस्ट में
र सवाल उत्पन्न हैं। उन्होंने
शी है कि बीसीसीआई को
शली है। वह प्रोसेसहन का
संशोधन प्रयोगशालाओं को
रणों और सॉफ्टवेयर पर
ना पड़ता है? अनुसंधान

और विकास को भी जीएसटी से मुक्त कर भारत के भविष्य के निर्माण में मदद की जाये। टाटा कार्स ने एरिस कॉम्पैक्ट सेडान लॉन्च की है। इसे विशेष रूप से व्यक्तिगत कार खरीदारों के लिए तैयार किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 5.29 लाख रुपये है। यह सेडान पेट्रोल और आईसीएनजी विकल्पों में उपलब्ध होगी। ग्राहकों को इसमें एएमटी सुविधा भी मिलेगी। एरिस सभी डीलरशिप पर उपलब्ध है। पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत 5.29 लाख रुपये और आईसीएनजी मॉडल की 6.29 लाख रुपये है। इसकी बुकिंग शुरू हो गई है और डिलीवरी 11 अक्टूबर से शुरू होगी। शैलेश चंद्रा, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, टाटा मोटर्स पैसंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने कहा, एरिस हमारे ग्राहकों की प्रगति और व्यक्तिगतता का प्रतीक है। इसे विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए तैयार किया गया है। एरिस में एलईडी हेडलैंप, डीआरएल और अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2026 से जैव ऊर्जा क्षेत्र में 2,800 करोड़ से ज्यादा के निवेश की उम्मीद: आईबीए

नई दिल्ली, एजेन्सी। ग्रेटर नोएडा में 22 से 24 मई तक आयोजित होने वाले रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2026 से जैव ऊर्जा क्षेत्र में बढ़े जाने पर पुंजी आने का अनुमान है। इंडियन बायोगैस एसोसिएशन के अनुसार यह राशि केंद्र सरकार की गोवर्धन योजना के कुल परिव्यय का लगभग 12 फीसदी है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य वेशकों और नीति-निर्माताओं को एक मंच पर कर कंस्ट्रिक्ट बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देना है। भारत के जैव ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को नई गति देने की को उम्मीद है। इंडियन बायोगैस एसोसिएशन (आईबीओए) ने कहा है कि अगले महीने आयोजित होने वाले रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो (आईआईई) 2026 से जैव ऊर्जा क्षेत्र में ₹2,800 करोड़ से अधिक के नए निवेश का रास्ता खुल सकता है। इस बार एक्सपो में जैव ऊर्जा या बायोगैस को भारत के हरित विकास के प्रमुख ध्येय के रूप में विशेष महत्व दिया जा रहा है।

हास्यकिताबें खोजें

केंद्र सरकार ने अगस्त, 2026 में गोबरधन योजना को मंजूरी दी थी, जो एक सितंबर 2026 से प्रभावी



मई है। वर्ष 2035-36 तक लागू रहने वाली इस योजना का उद्देश्य देश में केंद्रित बायोसिटी (सीबीजी) के उत्पादन को करीब दस गुना बढ़ाना, वर्ष 2026 पैमाने पर निजी निवेश जुटाना और देश में संसाधनों के महत्तम उपयोग वाली जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। आईबीएफ के अनुसार, आईआई-2026 में निवेशकों, परियोजना डेवलपर, प्रौद्योगिकी दाताओं और नीति-निर्माताओं को एक मंच पर लाकर नीतिगत पहल को बड़े पैमाने की परियोजनाओं में बदलने में मदद मिल सकती है। इससπο में इस बार जैव ऊर्जा मंडप अबतक का सबसे बड़ा होगा, जिसमें 35 की तुलना में 35 परियोजना अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे।

संक्षिप्त

समाचार

हूती हमलों के मद्देनजर सऊदी अरब की सुरक्षा में सहयोग करेंगे पाकिस्तान, तुर्किये

इस्लामाबाद , एजेंसी। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने यमन के हूती विद्रोहियों के हालिया हमलों के मद्देनजर



‘मक्का रक्षा गठबंधन’ के तहत सऊदी अरब की सुरक्षा में सहयोग करने का संकल्प लिया है. पाकिस्तान की सेना ने शनिवार को यह जानकारी दी. तीनों देशों ने पिछले महीने एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें सामूहिक रक्षा की व्यवस्था की गई है. समझौते के अनुसार, किसी एक देश पर सशस्त्र हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. सेना के एक बयान के अनुसार, तीनों देशों के रक्षा बलों के प्रमुखों और ‘चीफ्स ऑफ जनरल स्टाफ’ की बैठक शुक्रवार को रियाद में हुई. बैठक में सऊदी अरब की सुरक्षा स्थिति और उसके सामने मौजूद खतरों की समीक्षा की गई. बयान में कहा गया, ‘‘ प्रतिभागियों ने सामूहिक रक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और सऊदी अरब की सुरक्षा, संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के तीनों देशों के संकल्प को दिखाया.‘‘ बयान के अनुसार, प्रतिभागियों ने पवित्र शहर मक्का तथा असेन्थ और आर्थिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए हमलों पर नाराजगी जताई. उन्होंने सऊदी अरब के सशस्त्र बलों की सतर्कता और विशेषर रवेयें की सराहना की. बैठक में तीनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग को और बढ़ाने तथा खुफिया जानकारी साझा करने, सैन्य समन्वय और क्षमताओं के एकीकरण को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई. सेना के अनुसार, प्रतिभागियों ने कहा कि रियाद में हुई बैठक तीनों देशों की रक्षा साझेदारी की महबूती और ‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को तत्काल प्रभावी सैन्य सहयोग में बदलने के साझा संकल्प को दर्शाती है. यह बैठक तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की न्यूयॉर्क में हुई मुलाकात के एक दिन बाद हुई. उस बैठक में उन्होंने सऊदी अरब के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा की थी. पाकिस्तान ने बुधवार को पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद को इस त्रिपक्षीय गठबंधन का पहला महासचिव नियुक्त किया था.

4.27 सेकंड में रूबिक्स क्यूब सेट कर बनाया विश्व रिकॉर्ड

बीजिंग, एजेंसी। चीन की 6 वर्षीय लियान युनजी (झिंझि) ने मात्र 4.27 सेकंड में 3×3×3 रूबिक्स क्यूब सेट करने का महिला वर्ग में वर्लड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने वर्लड क्यूब एसोसिएशन की प्रतियोगिताओं में यह कीर्तिमान स्थापित किया। सिचुआन प्रांत के चेंगदू की रहने वाली झिंझि प्रतिदिन 2 से 3 घंटे तक रूबिक्स क्यूब का अभ्यास करती है। उन्होंने रूबिक्स क्यूब के लिए 1,300 से ज्यादा एल्गोरिदम पर महारत हासिल की है। रूबिक्स क्यूब को सबसे कम समय में हल करने का रिकॉर्ड पोलैंड के टियोडोर जाजडर के नाम है, जिन्होंने इसे 2.76 सेकंड में हल किया है।

अमेरिका के अल्बामा में टिकटोंक ने 958 करोड़ रुपये का समझौता किया

अल्बामा, एजेंसी। टिकटोंक और उसकी पैरेंट कंपनी बाइट डॉस ने अमेरिकी राज्य अल्बामा के साथ 100 मिलियन डॉलर (958 करोड़ रुपये) का ऐतिहासिक समझौता किया है, जिससे किशोरों में सोशल मीडिया की लत और उनके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा टल गया है। इस समझौते के तहत, अल्बामा में किशोरों के ऐप इस्तेमाल करने पर कई सख्त पाबंदियां लागू की जाएंगी।

55 महीने में पहली बैठक: यूएस में जर्मनी-रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात, 20 मिनट में ईयू से नाटो तक बातचीत

न्यूयार्क, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर शनिवार को जर्मनी और रूस के विदेश मंत्रियों की आमने-सामने मुलाकात हुई। रूस के यूक्रेन पर 2022 में पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू करने के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच यह पहली ऐसी सीधी मुलाकात मानी जा रही है। यह बैठक ऐसे समय हुई है जब यूरोपीय संघ और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसके कुछ ही देर बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया।

बैठक में जर्मन विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने रूस से जर्मनी, यूरोप और नाटो के साथ तनाव बढ़ाने वाली अपनी ‘खतरनाक राह’ छोड़ने की अपील की। जर्मन प्रतिनिधिमंडल के एक अधिकारी के मुताबिक, वाडेफुल ने कहा कि जर्मनी रूस के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए रूस के नेतृत्व को यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की वास्तविक इच्छा दिखानी होगी। हाल के हफ्तों में रूस और जर्मनी के रिश्तों में तनाव और बढ़ा है। पिछले महीने लीपजिग एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की कोशिश हुई थी। जर्मनी ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद दोनों देशों की ओर से एक-दूसरे

के खिलाफ जवाबी कदम भी उठाए गए। जर्मन समाचार एजेंसी डीपीए के मुताबिक, दोनों विदेश मंत्रियों की करीब



20 मिनट तक बातचीत हुई। बैठक के लिए जगह रूसी पक्ष की ओर से उपलब्ध कराई गई थी। बातचीत खत्म होने पर दोनों मंत्रियों ने एक-दूसरे से हाथ भी मिलाया।

वाडेफुल से मुलाकात के बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर पहुंचे। अपने

भाषण में उन्होंने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस का पक्ष रखा और पश्चिमी देशों पर जमकर निशाना साधा। जर्मनी भी उनके निशाने पर रहा। लावरोव ने खास तौर पर जर्मनी और जापान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने की चर्चा का विरोध किया। अमेरिका लंबे समय से जर्मनी, जापान और भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दिए जाने का समर्थन करता रहा है।

‘पश्चिम अपने विशेषाधिकार बचाने में लगा है: नाटो और अमेरिका की आलोचना करते हुए लावरोव ने कहा कि पश्चिम अब भी ‘अपने विशेषाधिकार बनाए रखने और अपने नियम दूसरों पर थोपने’ की कोशिश कर रहा है, जबकि दुनिया में भू-राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हमारी आंखों के सामने एक अधिक न्यायपूर्ण, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभर रही है।’ रूस ब्रिक्स समेत कई ऐसे अंतरराष्ट्रीय समूहों का हिस्सा है, जिन्हें लावरोव पश्चिमी व्यवस्था के विकल्प के तौर पर पेश करते रहे हैं। मास्को भी लगातार यह संदेश देने की कोशिश करता रहा है कि यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के साथ टकराव के बावजूद वैश्विक मंच पर रूस की स्थिति मजबूत बनी हुई है।

87 साल की महिला के खिलाफ पुलिस के एक्शन से हिल गया पूरा स्पेन, सरकार भी सिस्टम बदलने को हुई मजबूर



मैड्रिड , एजेंसी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में शनिवार को हजारों लोगों ने 87 साल की मैरीकारमेन अबासकल को घर से निकाले जाने के विरोध में मार्च निकाला. प्रदर्शनकारियों ने किरायेदारों को ज्यादा सुरक्षा देने, बढ़ते किराए पर रोक लगाने और लोगों को घर से निकालाना मुश्किल बनाने की मांग की. इस घटना ने 2027 के आम चुनाव से पहले स्पेन के गंभीर आवास संकट को फिर चर्चा में ला दिया है. मैरीकारमेन अबासकल को बुधवार को उनके घर से निकाला गया था. वह करीब 70 साल से इसी घर में रह रही थीं.

पुलिस ने उनके फ्लैट का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला. उस समय उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती

कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने उनकी बेदखली को सामाजिक त्रासदी बताया है. सरकार अगले कैबिनेट बैठक में मैरीकारमेन डिक्की लाने की तैयारी कर रही है. इसमें किराए के समझौतों को अपने-आप आगे बढ़ाने और बेदखली पर और पाबंदियां लगाने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं. हालांकि, संसद में सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसलिए प्रस्ताव का पास होना तय नहीं है. मैरीकारमेन की तस्वीरें सामने आने के बाद स्पेन में आवास संकट को लेकर गुस्सा बढ़ गया. शनिवार के प्रदर्शन में लोग चाबियां बजाते, सीटी बजाते और नारे लगाते हुए मध्य मैड्रिड से गुजरे. एक बैनर पर लिखा था- अगली मैरीकारमेन आप हो सकती हैं. सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, प्रदर्शन में करीब 25 हजार लोग शामिल हुए. वहीं, आयोजकों ने दावा किया कि करीब 3 लाख लोगों ने मार्च में हिस्सा लिया. मैरीकारमेन के मुताबिक, जिस रियल एस्टेट कंपनी ने उनकी संपत्ति खरीदी, उसने उनका किराया 275% बढ़ाकर 2,650 यूरो कर दिया था. इसके बाद वह घर का बड़ा हुआ किराया नहीं दे सकीं. अस्पताल से जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की. उन्होंने कहा कि उनके साथ जो हुआ, वह दूसरों के साथ न हो और कानून में बदलाव के लिए लोग आवाज उठाएं. बैंक ऑफ स्पेन के मुताबिक, करीब 5 करोड़ आबादी वाले स्पेन में 7 लाख घरों की कमी है. देश में सरकारी आवास भी कम है. पर्यटन और बढ़ती आबादी के कारण घरों की मांग और किराए दोनों बढ़े हैं.

नेपालमें एक और त्रासदी: हिमलुंग हिमाल बेस कैंप में अवानक हिमस्खलन, 10 लोग लापता; कई दिन से हो रही थी बर्फबारी

काठमांडो , एजेंसी। नेपाल के पश्चिमी हिस्से में तिब्बत की सीमा के पास स्थित हिमलुंग हिमाल के बेस कैंप में रविवार सुबह भीषण हिमस्खलन हुआ। इस हादसे के बाद कम से कम 10 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। लापता लोगों में अलग-अलग पर्वतारोहण अभियानों से जुड़े लोग शामिल हैं। अभियान आयोजकों के मुताबिक, दो लापता लोग रसोई में काम करने वाले कर्मचारी हैं। इलाके में पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी हो रही थी और खराब मौसम के कारण पर्वतारोहण अभियान पहले ही मुश्किल हो गए थे। अभियान आयोजक मिममा ग्यालजे शेरापा के मुताबिक, हिमस्खलन रविवार सुबह आया। उन्होंने बताया कि उनके रसोई कर्मचारियों में से दो लोग भी लापता हैं। पिछले सप्ताह मौसम को लेकर चेतावनी जारी होने के बाद पर्वतारोहण दल और रस्सी लगाने वाली टीम पहाड़ की ढलानों से नीचे तौट आई थीं। हालांकि, कुछ लोग वहां रुक गए थे। रविवार को आए हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद कम से कम 10 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है। ये सभी लोग अलग-अलग अभियान कंपनियों से जुड़े हुए थे। हिमलुंग हिमाल क्षेत्र में पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी हो रही थी। खराब मौसम के कारण पर्वतारोहियों को शरद ऋतु में होने वाली चढ़ाई से पीछे हटना पड़ा था। लगातार बारिश और बर्फबारी ने नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हालात और मुश्किल कर दिए हैं। मौसम बिगड़ने के बाद पर्यटन अधिकारियों ने ट्रेकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों को रोकने की सलाह दी है। पर्यटन विभाग ने भी लोगों को मौसम साफ होने तक पर्यटन गतिविधियां स्थगित रखने को कहा है। हिमलुंग हिमाल की ऊंचाई 7,126 मीटर है और यह नेपाल के मनांग जिले में स्थित है। ऊंचाई पर पर्वतारोहण का अनुभव हासिल करने वाले पर्वतारोहियों के बीच यह चोटी काफी लोकप्रिय है। हालांकि, यहां पहुंचना आसान नहीं है। हिमलुंग हिमाल क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए अतिरिक्त अनुमति की जरूरत होती है। ऐसे में किसी हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान चलाना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लापता लोगों की तलाश के बीच खराब मौसम इस चुनौती को और बढ़ा रहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने मौसम तंत्र का असर नेपाल के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी हो रही है, जबकि पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। शुक्रवार से खराब मौसम के कारण नेपाल में कई जगह सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने कुछ सड़कों को यातायात के लिए बंद भी किया है। लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण कई ट्रेकिंग मार्ग प्रभावित हुए हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का रूस ने समर्थन किया

न्यूयॉर्क, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का जोरदार समर्थन किया. साथ ही पश्चिमी देशों के पुनः प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया के नेताओं को संबोधित करते हुए लावरोव ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी सुधार से परिषद और उसके परमानेंट सदस्यों के खास अधिकार कम नहीं होने चाहिए. मास्को के उसूलों वाले रुख को बताते हुए उन्होंने जोर दिया कि सुधारों में पश्चिमी देशों को और सीटें देने से बचना चाहिए.

लावरोव ने कहा, ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार में पश्चिमी देशों, खासकर जर्मनी और जापान को अतिरिक्त सीट नहीं दी जा सकती, जो अब सैन्यवाद और बदला लेने की राह पर हैं.’ ज्यादा सबको साथ लेकर चलने वाले और भौगोलिक रूप से संतुलित वैश्विक वास्तुकला की वकालत करते हुए रूसी विदेश मंत्री ने ग्लोबल साउथ से पुनः प्रतिनिधित्व बढ़ाने का जोरदार समर्थन किया.

लावरोव ने कहा, ‘हम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के पक्ष में हैं. हम परमानेंट सीट के लिए ब्राजील और भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं. और साथ ही, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमें इजराइली आम सहमति और एसईएटी घाषणा के अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप के हितों को पूरा करना चाहिए.’ रूस समेत ब्रिक्स देशों ने पहले नई दिल्ली डिक्लेरेशन में संयुक्त राष्ट्र जिसमें

सुरक्ष परिषद भी शामिल है, में ब्राजील और भारत की बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीदों के लिए अपना सपोर्ट दोहराया था. संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में चल रही आम बहस के दौरान इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए दुनिया भर के नेताओं ने इस बात



पर सहमति जताई कि परिषद को आज की दिग्योर्पाॉलिटिकल और इकॉनॉमिक हकीकतों को दिखाने की तुरंत जरूरत है. मॉरिशस ने अपने भाषण के दौरान भारत की दावेदारी का साफ तौर पर समर्थन किया. मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने नई दिल्ली का साथ देते हुए कहा, ‘हम कार्डसिल सुधार पर जी4 और एल69 की बातों का सपोर्ट करते हैं, और हम ग्लोबल मामलों में भारत की कंस्ट्रक्टिव भूमिका के हिसाब से परमानेंट सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए अपना सपोर्ट दोहराते हैं.’ भारत को अपने सपोर्ट के साथ-साथ, मॉरिशस ने कॉमन अफ्रीकन पोजीशन का भी समर्थन किया, जिसमें सही रीजनल रिप्रेजेंटेशन, नए परमानेंट मेंबर्स के लिए समान अधिकार और छोटे

आइलैंड डेवलपिंग देशों के लिए खास जगह देने पर जोर दिया गया. पुर्तगाल ने भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की मांग को और बढ़ाया, पुर्तगाली प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो ने अफ्रीका, ब्राजील और भारत के लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेशन वाली एक ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव कार्डसिल की वकालत की. नई दिल्ली की महत्वाकांक्षाओं को चार देशों के जी4 अलायंस के जरिए अप्रत्यक्ष सपोर्ट मिला. मार्शल आइलैंड्स की प्रेसिडेंट हिल्डा ह्वेन ने यह सपोर्ट करते हुए कहा, ‘मार्शल आइलैंड्स संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबरशिप हासिल करने के लिए जापान और उसके जी4 पार्टनर्स को अपने लंबे समय से सपोर्ट की पुष्टि करता है.’ जबकि जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने अपने भाषण में अलग-अलग जी4 कैडिडेट का नाम नहीं लिया, ओक्यो ने रिफॉर्म को सबसे आगे रखा. तेजी से स्ट्रक्चरल बदलावों का आग्रह करते हुए ताकाइची ने कहा, ‘हमें इसे बिना देर किए एक ऐसे स्ट्रक्चर में बदलने की जरूरत है जो एएसी मांसू में अंतरराष्ट्रीय समदाय की मौजूदा हकीकत को दिखाए.’ उन्होंने आगे परमानेंट और नॉन-परमानेंट दोनों कैटेगरी में विस्तार की वकालत की, और मेंबर देशों के बीच व्यापक सहमति पर ध्यान दिया. अन्य अंतरराष्ट्रीय हस्तियों ने कैडिडेट देशों का नाम बताए बिना रीजनल बराबरी पर जोर दिया. फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टेब ने वीटो पावर कंस्ट्रेशन को मना करते हुए अफ्रीका, एशिया-पैसिफिक और लैटिन अमेरिका के लिए परमानेंट स्लॉट का समर्थन किया, जबकि सेंट लूसिया के प्राहम मिनिस्टर फिलिप जे. पियरे ने लंबी बातचीत को तुरंत खत्म करने की अपील की।

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने किया बड़ा दावा

अपने निजी टेलीग्राम चैनल पर दावा किया कि ‘दर्जनों राजनयिक’ लावरोव से मिलने पहुंचे और उन्होंने रूस का हाथ मिलाकर आभार जताया। इस बीच यूक्रेन युद्ध में हवाई हमले भी तेज हो गए हैं। पिछले साल से जमीनी मोर्चे पर बड़े बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन हाल के महीनों में रूस ने यूक्रेन पर कूज और बैलिस्टिक मिसाइलों, भारी ग्लाइड बॉम और जेट इंजन वाले ड्रोन से हमले बढ़ाए हैं। दूसरी ओर, यूक्रेन भी लंबी दूरी के ड्रोन के जरिए रूस की तेल रिफाइनरियां और कारोबारिक टिकानों को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार को रूस के हमलों में चार लोगों की मौत हुई। वहीं रूसी अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में तीन लोग मारे गए। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। मास्को इसे अब भी ‘विशेष सैन्य अभियान’ कहता है और उसका कहना है कि इसका मकसद रूस की सुरक्षा तथा रूसी भाषी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है।

बैंकोंक में बाढ़- गाड़ियां डूबीं, बसों में भरा पानी: सड़कों पर सांप घूम रहे, 48 घंटे में 300 मिमी बारिश

बैंकॉक, एजेंसी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां डूब गई और बसों में भी पानी घुस गया। कई इलाकों में लोग कमर तक भरे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। इस बीच, बाढ़ के पानी में सांप दिखाई देने की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। प्रशासन ने शहर के सभी 50 जिलों को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है।

मौसम विभाग ने 27 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। बैंकॉक के कुछ इलाकों में शनिवार तक 48 घंटे के दौरान करीब 300 मिमी बारिश दर्ज की



गई। लगातार बारिश से प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गईं। बाढ़ के कारण पूर्वी बैंकॉक के कई इलाकों में लोग घुटनों और कमर तक भरे पानी से गुजरते नजर आए। कुछ लोग पानी में फसी मोटरसाइकिलों को धकेलते दिखे, जबकि कई सड़कों पर कारें आधी डूबी हुई थीं। जलभराव वाले इलाकों में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कुछ दुकानों में जरूरी सामान की कमी भी सामने आई है। लोग खाने-पीने की चीजें खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से घरबाने की जरूरत नहीं होने की अपील की है। सोमवार को स्कूल बंद रखने का फैसला भी लिया गया है। बैंकॉक प्रशासन के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 233 अस्थायी राहत शिविर बनाए गए हैं। इनमें करीब 4200 लोग शरण ले चुके हैं। प्रधानमंत्री अनुदिन चार्नविर्माकुल लंदन का दौरा बीच में छोड़कर बैंकॉक लौट आए हैं।

जयशंकर की कनाडा, मेक्सिको और वेनेजुएला के विदेश मंत्रियों से मुलाकात, ऊर्जा और एआई पर हुई चर्चा

वाशिंगटन, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान भारत की कूटनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को अलग-अलग बैठकों में कनाडा, मेक्सिको और वेनेजुएला के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इन बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों, आपसी सहयोग और मौजूदा क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। जयशंकर ने इन मुलाकातों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि अलग-अलग देशों के साथ भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद के साथ बैठक की। उन्होंने इस मुलाकात को उपयोगी बताया। जयशंकर ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। यह मुलाकात ऐसे समय हुई जब भारत

और कनाडा के संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में दोनों पक्षों की बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

जयशंकर ने मेक्सिको के विदेश मंत्री रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेज के साथ भी बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। जयशंकर ने इस बैठक की जानकारी भी साझा की। भारत और मेक्सिको के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग रहा है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई यह बैठक दोनों देशों के बीच संपर्क को आगे बढ़ाने का अवसर बनी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में बैठक में उठाए गए प्रत्येक मुद्दे का अलग-अलग विवरण नहीं दिया गया है।

वेनेजुएला के साथ ऊर्जा सहयोग क्यों अहम रहा: जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वेनेजुएला के विदेश मंत्री फेलिक्स प्लासेंसिया गोंजालेज से मुलाकात



की। उन्होंने बैठक को अच्छा बताया। जयशंकर के अनुसार, भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा संबंधों में तेजी आ रही है। दोनों देशों के बीच सहयोग के दूसरे क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा मौजूदा क्षेत्रीय मुद्दे भी बातचीत का हिस्सा रहे। ऊर्जा क्षेत्र भारत और वेनेजुएला के संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए इस बैठक में इस मुद्दे पर विशेष ध्यान रहा।

इन द्विपक्षीय बैठकों से पहले जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई को लेकर भारत की सोच भी रखी। उन्होंने कहा कि हर देश को अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के अनुसार अपना एआई तंत्र तैयार करने का अधिकार है। इसके लिए देश अपने मॉडल विकसित कर सकते हैं और उन्हें इस्तेमाल की रणनीति तय कर सकते हैं। भारत एआई को ग्लोबल साउथ के साथ अपनी साझेदारी के एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता

है। जयशंकर ने एआई को मानव सशक्तीकरण, आर्थिक समृद्धि और बड़े पैमाने पर लोगों की समस्याओं के समाधान में बदलाव लाने वाली तकनीक बताया। उन्होंने तकनीक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और अलग-अलग संस्कृतियों को समझने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने फरवरी में एआई इपेक्ट समिट की मेजबानी की थी, जिसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ और प्रमुख लोग शामिल हुए थे। जयशंकर की इन बैठकों में भारत के अलग-अलग साझेदार देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिखाई दिया। कनाडा के साथ संबंधों को नई ऊंचाई देने, मेक्सिको के साथ द्विपक्षीय संपर्क बढ़ाने और वेनेजुएला के साथ ऊर्जा सहयोग को गति देने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही एआई को लेकर भारत ने अपनी प्राथमिकताओं को भी वैश्विक मंच पर सामने रखा।

